

(d) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) to (d) As per the guidelines issued by the Department of Public Enterprises in 1993, the Central Public Sector Enterprises have already been authorised to conclude the long term wage settlements with their workers' unions and implement them.

इस्पात के उत्पादन में वृद्धि

774. श्री अनन्तराय देवशंकर दवे: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस्पात के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उनके मंत्रालय के बजट आवंटन में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस्पात के और अधिक उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

इस्पात मंत्री और खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य): (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार ने देश में इस्पात के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण और विस्तार संबंधी कार्यक्रम शुरू गए किए हैं। निजी क्षेत्र में इस्पात के उत्पादन की अतिरिक्त क्षमता सृजित करने की सुविधा के लिए तथा इसे प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने भी विभिन्न नीतिगत उपाय किए हैं। ये उपाय निम्नानुसार हैं:—

(1) सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची से लोहा और इस्पात को निकालना।

(2) लोहा तथा इस्पात उद्योग को अनिवार्य लासेंसिंग के प्रावधानों से छूट देना।

(3) विदेशी निवेश के प्रयोजन से लोहा और इस्पात को उच्च प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों की सूची में शामिल करना।

(4) लोहा और इस्पात के मूल्य-निर्धारण और वितरण पर से नियंत्रण समाप्त करना।

(5) पूंजीगत माल के आयात पर शुल्क को कम करना।

(6) आयात एवं निर्यात नीति का उदारीकरण।

Negative List for MNCs

775. **SHRI SATISH AGARWAL:** Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether attention of the Government is drawn to the news-item appearing in the 'Times of India' dated 27th June, 1996, under the caption "Negative list for MNCs may be extremely narrow"; and

(b) if so, whether the list has since been drawn up and by when it will be laid on the Table of the House?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI BOLLA BULLI RAMAIAH): (a) Yes, Sir.

(b) As per available information, no such list has been drawn up so far.

National Commission for Minorities

776. **SHRI V. NARAYANASAMY:** Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the National Commission for Minorities is functioning without sufficient number of members;

(b) if so, the steps taken by Government to fill up these posts;

(c) the number of reports submitted by the National Commission for Minorities during last two years and how many of them have been accepted by Government; and

(d) what is total amount provided for this Commission?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA): (a) and (b) With the